4 मौतें, सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी... संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री बंद, मगर चंद्रशेखर ने किया घुसने का ऐलान

https://www.aajtak.in/uttar-pradesh/story/up-sambhal-violence-entry-of-outsiders-banned-till-december-1-complaint-lodged-in-nhrc-akhilesh-yadav-days-conspiracy-to-spread-tension-in-the-name-of-survey-ntc-dskc-2105865-2024-11-25

संभल हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई. डीएम के आदेश पर 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, इसे लेकर शहर की सीमा सील कर दी गई है. वहीं, मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि दो महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है, हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

aajtak.inसंभल ,25 नवंबर 2024,(अपडेटेड 25 नवंबर 2024, 7:01 AM IST)

उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को भारी हिंसा हुई. जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 सुरक्षाकर्मियों और प्रशासन के चार कर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए. इस दौरान पत्थर-ईंटें फेंके गए, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया

20 पुलिसकर्मी घायल, डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर

मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि उपद्रवियों ने गोलियां चलाईं, एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी, सीओ को छर्रे लगे और हिंसा में 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल के सिर में भी गंभीर चोट आई है, जबकि डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिला प्रशासन ने 25 नवंबर को कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है. डीएम के आदेश पर 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, इसे लेकर शहर की सीमा सील कर दी गई है.

संभल हिंसा में इन 4 लोगों की गई जान

संभल हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई. नौमान और बिलाल अंसारी को रात 11 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया. हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है. एक निजी संस्था ने संभल में पुलिस की फायरिंग से 4 युवकों की मौत का आरोप लगाते हुए वीडियो भी आयोग को भेजा गया है.

चंद्रशेखर आजाद ने किया आज संभल जाने का ऐलान

एक ओर संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, वहीं, भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वह सोमवार यानी आज संभल जाएंगे और मृतकों के परिजनों से मिलेंगे. चंद्रेशखर आजाद ने X पर लिखा कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं. यह कोई मिथक नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है, जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. चाहे वह एससी/एसटी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या सीएए विरोधी आंदोलन... हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है. मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा.

अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट में कहा कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साज़िश का 'सर्वोच्च न्यायालय' तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाज़ों को ले गए, उनके ख़िलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुक़दमा दर्ज हो. उनके ख़िलाफ़ 'बार एसोसिएशन' भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे. अखिलेश ने कहा कि उप्र शासन-प्रशासन से न कोई उम्मीद थी, न है.

हिंसा में सड़क पर बिखरे चप्पल, ईंटें और पत्थर

हिंसा की तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को इमारतों की छतों और शाही जामा मस्जिद के सामने से पुलिस पर पथराव करते हुए देखा गया. एक गली में बड़ी संख्या में चप्पलें, ईंटें और पत्थर बिखरे हुए थे. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ पुलिसकर्मी एक गली की ओर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है. एक क्लिप में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार को पथराव करने वालों से हिंसा न करने का आग्रह करते हुए देखा जा सकता है. उन्हें अपने मेगाफोन पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इन राजनेताओं के लिए अपना भविष्य खराब मत करो.

2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया

संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया है, किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे किसी की जान जा सकती हो. 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनके पास से कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं. जिस जगह पर फायरिंग हुई, वहां से कई अलग-अलग बोर के गोले बरामद किए गए हैं. हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से भी हथियार बरामद किए गए हैं.

हिंसा में शामिल लोगों पर लगेगा NSA

नखासा थाना क्षेत्र के एक घर से फायरिंग हुई, जहां से दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. मंगलवार से ही संभल में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जब एक स्थानीय अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था. याचिका में दावा किया गया था कि उस जगह पर हरिहर मंदिर था. अंजनेय कुमार सिंह ने

कहा कि दो महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है, हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

Lagacharla Violence: NHRC Team Visits Sangareddy Jail

https://indtoday.com/lagacharla-violence-nhrc-team-visits-sangareddy-jail/

Telangana NewsTop Stories

By IND Today News Desk Last updated Nov 24, 2024

Sangareddy/Hyderabad, Nov 24 (Maxim News): A team from the National Human Rights Commission (NHRC) visited Sangareddy Central jail as part of its investigation into the Lagacharla incident. The eight-member NHRC team interacted with the accused detained in connection with the case and gathered detailed information about their circumstances.

The jail currently houses 19 accused individuals, including A2 Suresh, who were questioned by the NHRC team. The visit aimed to ensure that the rights of the detainees are being upheld and to assess the conditions in the prison. The NHRC team's inquiry is part of their broader effort to address any potential human rights violations and ensure accountability in the ongoing investigation into the Lagacharla case. (Maxim News)

Manipur civil bodies demand justice for Jakuradhor victims

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2024/11/24/ces16-mn-memorandum.html

https://www.ifp.co.in/manipur/manipur-violence-seven-csos-seeks-justice-for-six-victims-of-jakuradhor-massacre

https://www.imphaltimes.com/news/manipur-based-organizations-demand-justice-for-jakuradhor-massacre-submit-memorandum-to-united-nations/

PTI Updated: November 24, 2024 18:58 IST

Imphal, Nov 24 (PTI) A prominent Manipur-based think tank and six other organisations on Sunday urged the United Nations to exert pressure on the central government to arrest the culprits behind the killing of three women and three children at Jakuradhor in Jiribam district.

In a memorandum to the UN secretary general, think tank Taragi Cheisu along with the other organisations demanded "immediate arrest and punishment of those involved in the Jakuradhor massacre of women and children under Geneva Convention Act 1960 and relevant domestic criminal laws."

The memorandum also called for the constitution of an independent judicial inquiry commission to investigate the killings, led by "not less than a retired Supreme Court judge," and the deputation of a UN special rapporteur to conduct a probe into the incident.

Additionally, the memorandum urged the National Commission for Women to visit Jakuradhor and come up with a white paper on the killings.

It also requested the National Human Rights Commission to visit the site and ensure justice for the victims, while further advocating for the repeal of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the state.

Some of the other organisations that submitted the memorandum include Youth Collective Manipur, Manipur Students Association Delhi, Manipur International Youth Centre, and others.

Manipur Civil Bodies Demand Justice For Jakuradhor Victims

https://www.republicworld.com/india/manipur-civil-bodies-demand-justice-for-jakuradhor-victims

Taragi Cheisu and six other groups asked the UN on Sunday to pressure India to arrest those responsible for killing three women and three children in Jiribam.

India News 2 min read Reported by: Digital Desk

Imphal: A prominent Manipur-based think tank, Taragi Cheisu, along with six other organisations, on Sunday urged the United Nations to pressure the Indian government into arresting those responsible for the brutal killing of three women and three children at Jakuradhor in Jiribam district.

In a memorandum addressed to the UN Secretary-General, the organisations demanded immediate action under the Geneva Convention Act, of 1960, and relevant domestic laws. They called for the arrest and punishment of the perpetrators of the "Jakuradhor massacre" and sought the formation of an independent judicial inquiry commission to investigate the killings. The organisations insisted that the inquiry be led by a retired Supreme Court judge and recommended the deputation of a UN special rapporteur to oversee the probe.

The memorandum also appealed to the National Commission for Women (NCW) to visit the site and release a detailed report on the killings. It further requested the National Human Rights Commission (NHRC) to ensure justice for the victims. Additionally, the groups urged for the repeal of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), citing its contentious role in Manipur.

The appeal to the UN was jointly submitted by organisations including the Youth Collective Manipur, Manipur Students Association Delhi, Manipur International Youth Centre, and others. They emphasised the urgency of addressing what they termed a gross violation of human rights.

The killings at Jakuradhor occurred amidst heightened ethnic tensions in Manipur. The region has long grappled with violence stemming from ethnic and political conflicts. The Armed Forces Special Powers Act, in effect in Manipur, has been a focal point of contention for years, with activists and local groups claiming it enables excesses by security forces.

Manipur organisations urge UN for immediate action and justice over Jiribam hostage killings

https://www.indiatodayne.in/manipur/story/manipur-youth-organisation-urges-un-for-immediate-action-and-justice-over-jiribam-hostage-killings-1126267-2024-11-24

Several organisations of Manipur, including youth bodies submitted a memorandum to the United Nations, demanding urgent action and justice for six internally displaced persons (IDPs), including an eight-month-old infant, who were killed in the Jakuradhor massacre in Jiribam, by alleged Kuki militants

Updated Nov 24, 2024, 5:55 PM IST

Several organisations of Manipur, including youth bodies submitted a memorandum to the United Nations, demanding urgent action and justice for six internally displaced persons (IDPs), including an eight-month-old infant, who were killed in the Jakuradhor massacre in Jiribam. The tragic incident, allegedly perpetrated by Kuki militants, has been denounced as a blatant violation of international humanitarian laws.

The organisations comprising of Yelhoumee Phurup, Taragi Cheishu, Solidarity Offered Unitedly for a Lustrated Society, Youth Collective Manipur, Nupi Union for Peace and Integrity, Manipur Students' Association Delhi, and Manipur International Youth Centre described the killings as a violation of the 'Martens Clause,' a key principle of customary international law, and called on the UN to hold the perpetrators accountable. Highlighting the severity of the crime, the memorandum sought immediate global intervention and proposed several measures to ensure justice:

Arrest and Prosecution: Immediate apprehension and trial of the Kuki militants under India's Geneva Conventions Act, 1960, and other applicable domestic laws.

Judicial Inquiry: Establishment of an independent Judicial Inquiry Commission led by a retired Supreme Court judge to investigate the massacre.

UN Investigation: Deployment of a UN Special Rapporteur to probe the incident.

Reports by National Commissions: Involvement of the Women and Child Commission of India to produce a comprehensive report under the POCSO Act, 2012, and the National **Human Rights Commission (NHRC)** to ensure justice for the victims.

Repeal of AFSPA: Immediate repeal of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), widely criticized for enabling human rights violations.

War Crimes Tribunal: Establishment of a tribunal under the UN Security Council to prosecute individuals responsible for war crimes, crimes against humanity, and acts of genocide or ethnic cleansing.

The memorandum underscores the urgency for the international community to address the killings, citing India's alleged inability to act independently. The organisations called for immediate UN intervention to safeguard human rights and uphold justice for the victims of this devastating atrocity.

Manipur नागरिक निकायों ने जकुराधोर पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की

https://jantaserishta.com/local/manipur/manipur-civic-bodies-demand-justice-for-jakuradhor-victims-3661607

Harrison24 Nov 2024 9:30 PM

Imphal इंफाल: मणिपुर के एक प्रमुख थिंक टैंक, तरागी चेइसू ने छह अन्य संगठनों के साथ मिलकर रविवार को संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वह जिरीबाम जिले के जकुरादोर में तीन महिलाओं और तीन बच्चों की नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित ज्ञापन में संगठनों ने 1960 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम और संबंधित घरेलू कानूनों के तहत तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने "जकुरादोर नरसंहार" के अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग की और हत्याओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की।

संगठनों ने जोर देकर कहा कि जांच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए और जांच की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की प्रतिनियुक्ति की सिफारिश की। ज्ञापन में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) से घटनास्थल का दौरा करने और हत्याओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करने की भी अपील की गई। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त, समूहों ने मणिपुर में इसकी विवादास्पद भूमिका का हवाला देते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को निरस्त करने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र को यह अपील यूथ कलेक्टिव मणिपुर, मणिपुर छात्र संघ दिल्ली, मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय युवा केंद्र और अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

NHRC seeks report on policy to check manufacturing of spurious liquor

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-demands-urgent-report-on-spurious-liquor-policy-following-deadly-hooch-tragedy/articleshow/115632814.cms

Nov 24, 2024, 11.21 PM IST

Berhampur: National Human Rights Commission (NHRC) has sought information from chief secretary Manoj Ahuja within eight weeks about the existing policy to check and prevent the manufacturing of spurious liquor, while hearing a petition on the hooch tragedy that claimed five lives in Ganjam district's Chikiti in Aug-Sept.

NHRC, in its order issued on Wednesday, also sought the standard operating procedure (SOP) for the treatment of persons who fall sick after consuming such liquor and details on compensation of the next of kin of the deceased.

The commission has also sought status reports from the Ganjam collector and Berhampur SP on compensation to the family members of the deceased and the case registered at K Nuagaon police station, respectively.

While hearing the plea by Radhakant Tripathy, an Odisha-based advocate and human rights activist, seeking the commission's intervention in the hooch tragedy, NHRC on Sept 9 directed the chief secretary, district magistrate and SP to file their action taken reports within six weeks.

Except the SP, the commission has not received any response from the chief secretary regarding his earlier direction. The commissioner has issued a reminder to Ahuja to submit the report.

In his response, the SP on Oct 29 said five persons died and several others fell sick due to the consumption of spurious liquor in Chikiti on Aug 20. The deceased were identified as Jura Behera, Lokanath Behera, Laxan Behera, Pradeep Behera and Baya Sethi. They had consumed liquor on Aug 19.

The post-mortem reports are yet to be received, police said. However, police said 10 people were arrested for allegedly selling the liquor illegally. Police registered a case in this regard and started an investigation, sources said. Police also informed the commission that the next of kin of the deceased have applied for compensation before the district legal services authority.

DECCAN CHRONICLE, Online, 25.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Team Investigates Attacks on Vikarabad Collector and Officials

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/nhrc-team-investigates-attacks-on-vikarabad-collector-and-officials-1841018

DC Correspondent 25 November 2024 12:15 AM

hyderabad: An eight-member team of National Human Rights Commission (NHRC) on Sunday collected details from arrested for the attacks on Vikarabad collector and revenue officials at Lagcharla, who are now housed in the Sangareddy Central prison. The NHRC team members recorded the statements of arrested accused B. Suresh.

The NHRC team members also verified the FIR registered against the accused and the reasons for the public hearing at Lagcharla turning violent, with the attack on collector Prateek Jain and other officials. The police have arrested more than 20 persons from Lagcharla for the incident. The public hearing was to be held over land acquisition in the village in the district.

NHRC team visits Lagacherla farmers in Sangareddy jail

https://telanganatoday.com/nhrc-team-visits-lagacherla-farmers-in-sangareddy-jail

Accompanied by Inspectors Rohit Singh and Yathi Prakash Varma, Deputy Registrar of Law Mukesh visited the jail. They will interact with the farmers and are later expected to address the media

By Telangana TodayPublished Date - 24 November 2024, 11:10 AM

sangareddy: Representatives of the National Human Rights Commission (NHRC) visited the Central Jail in Sangareddy on Sunday to interact with 21 Lagacherla farmers who were jailed by the police.Accompanied by Inspectors Rohit Singh and Yathi Prakash Varma, Deputy Registrar of Law Mukesh visited the jail. They will interact with the farmers and are later expected to address the media.

The NHRC team visited Lagacherla village on Saturday and interacted with the farmers there.

NHRC Team Visits Sangareddy Jail to Investigate Lagacharla Incident Kausalya

https://www.thehansindia.com/news/cities/khammam/brs-rallies-support-for-lagacharla-victims-923656

Rachavelpula Hans News Service | 24 Nov 2024 12:31 PM IST

sangareddy: A team from the National Human Rights Commission (NHRC) visited Sangareddy Central Jail as part of its investigation into the Lagacharla incident. The eight-member NHRC team interacted with the accused detained in connection with the case and gathered detailed information about their circumstances.The jail currently houses 19 accused individuals, including A2 Suresh, who were questioned by the NHRC team. The visit aimed to ensure that the rights of the detainees are being upheld and to assess the conditions in the prison.

The NHRC team's inquiry is part of their broader effort to address any potential human rights violations and ensure accountability in the ongoing investigation into the Lagacharla case.

NHRC की टीम ने संगारेड्डी जेल में लागाचार्ला किसानों से मुलाकात की

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-team-meets-lagacharla-farmers-in-sangareddy-jail-3661234

Tulsi Rao24 Nov 2024 5:18 PM

Sangareddy संगारेड्डी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के प्रतिनिधियों ने रविवार को संगारेड्डी की सेंट्रल जेल का दौरा किया और पुलिस द्वारा जेल में बंद 21 लागाचेरला किसानों से बातचीत की। इंस्पेक्टर रोहित सिंह और यति प्रकाश वर्मा के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ लॉ मुकेश ने जेल का दौरा किया। वे किसानों से बातचीत करेंगे और बाद में मीडिया को संबोधित करेंगे। एनएचआरसी की टीम ने शनिवार को लागाचेरला गांव का दौरा किया और वहां किसानों से बातचीत की।

NHRC की टीम ने संगारेड्डी जेल में लागाचार्ला किसानों से मुलाकात की

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc--3661047

Payal24 Nov 2024 4:02 PM

Sangareddy,संगारेड्डी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) NHRC के प्रतिनिधियों ने रविवार को संगारेड्डी की सेंट्रल जेल का दौरा किया और पुलिस द्वारा जेल में बंद 21 लागाचेरला किसानों से बातचीत की। इंस्पेक्टर रोहित सिंह और यति प्रकाश वर्मा के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ लॉ मुकेश ने जेल का दौरा किया। वे किसानों से बातचीत करेंगे और बाद में मीडिया को संबोधित करेंगे। एनएचआरसी की टीम ने शनिवार को लागाचेरला गांव का दौरा किया और वहां किसानों से बातचीत की।

NHRC टीम ने लागाचार्ला घटना की जांच के लिए संगारेड्डी जेल का दौरा किया

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-team-visits-sangareddy-jail-to-investigate-lagacharla-incident-3660963

Tulsi Rao24 Nov 2024 3:40 PM

Sangareddy संगारेड्डी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक टीम ने लगचर्ला घटना की जांच के तहत संगारेड्डी सेंट्रल जेल का दौरा किया। आठ सदस्यीय एनएचआरसी टीम ने मामले के सिलसिले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से बातचीत की और उनकी परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई।इस समय जेल में ए2 सुरेश समेत 19 आरोपी बंद हैं, जिनसे एनएचआरसी टीम ने पूछताछ की। इस दौरे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है और जेल की स्थितियों का आकलन करना था।एनएचआरसी टीम की जांच किसी भी संभावित मानवाधिकार उल्लंघन को संबोधित करने और लगचर्ला मामले की चल रही जांच में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उनके व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

TELEGRAPH, Online, 25.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Rights group seeks NHRC intervention after BSF's alleged 'assault' in Bengal

https://www.telegraphindia.com/west-bengal/rights-group-seeks-national-human-rights-commission-intervention-after-border-security-force-alleged-assault-in-bengal/cid/2065613

The organisation claimed such deployments result in unnecessary interference in the daily lives of residents and their livelihood

Subhasish Chaudhuri, Alamgir Hossain Calcutta, Behrampore Published 24.11.24, 10:52 AM

A Bengal-based human rights organisation, Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), has appealed to the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene and prevent Border Security Force (BSF) personnel from being posted 8km inside villages from the international border.

The organisation claimed such deployments result in unnecessary interference in the daily lives of residents and their livelihood.

In its petition to the NHRC, with copies sent to the director general of the BSF, the Union ministry of home affairs, and the Bengal police, apart from others, MASUM highlighted a recent incident of alleged “brutal assault” in Murshidabad’s Jalangi area to stress their point.

On November 8, a young fisherman, Anowar Mondal, was reportedly beaten mercilessly by a BSF company commander while fishing near Toltoli ferry ghat. The officer allegedly confiscated and damaged Mondal’s identity card, issued by the Bengal government, rendering it unusable. Senior BSF officials of the South Bengal Frontier, however, refuted the allegations claiming it was “far from truth”.

However, according to the petition, Mondal, a 20-year-old resident of Char-Parashpur village under Ghospara Gram Panchayat, was fishing with others around 6am when the incident occurred. The BSF commander, identified as Shibram from Battalion-46 (Forajipara border outpost), allegedly abused him verbally before assaulting him with a ruler, warning him not to return to the area for fishing.

“This incident not only caused significant physical harm to the young fisherman but also jeopardised his livelihood, instilling fear within his community,” said MASUM secretary Kirity Roy.

Mondal lives in Char-Parashpur, an alluvial stretch of land formed on the other side of the Padma river after his original village was lost to erosion. The villagers, dependent on

fishing for their livelihood, rely on BSF clearance to access these areas as they lack the know-how of border demarcations in rivers.

To prevent their harassment, the state government has issued identity cards to these fishermen.

However, Roy alleged that “high-handedness” by BSF personnel has made the villagers live in constant fear.

“The actions of the BSF violate fundamental human rights and constitutional protections, including those ensured under the provisions Article 21 (right to life and personal liberty), Article 19 (freedom of profession), and Article 22 (protection against arbitrary arrest and detention),” he said.

Mondal sought medical treatment at a local hospital and later filed a general diary with the Jalangi police station, which the cops had initially refused. However, no action has been taken by the police.

Contacted, Domkal SDPO Shubham Bajaj claimed ignorance about the incident and promised to look into the matter, including an alleged refusal by Jalangi police to register a complaint initially.

A MASUM fact-finding team visited the area to speak to Mondal and other villagers, who reported widespread fear of the BSF.

Refuting the allegations, BSF South Bengal Frontier DIG Nilotpal Pandey said: “Anowar was observed at night crossing beyond the domination line in the riverine, which is an unfenced stretch of the border. Being familiar with the terrain as a regular visitor, he is well aware of the protocols. BSF personnel maintain an entry point for villagers who frequently access the area, but some individuals attempt to bypass it. Typically, no one ventures into such stretches at night unless driven by illegal intentions. A day before the incident, Anowar Mondal was also spotted beyond the domination line under suspicious circumstances, prompting our personnel to impose restrictions on his movement due to repeated violations.”

“However, his allegations of assault are baseless and can be verified through independent sources,” Pandey said, adding that allegations of damaging his identity card would be looked into.

The incident has reignited debates over the Centre’s decision to extend the BSF’s jurisdiction to a 50km-radius from international border in states like Bengal, Assam, Punjab, Gujarat and Rajasthan.

The Centre called it necessary to curb smuggling and enhance border security.

However, Bengal chief minister Mamata Banerjee and her Trinamool Congress government called it a “direct attack on the federal structure” and an encroachment on state powers. The TMC has also alleged that the move is “politically motivated” and aimed at undermining regional governments opposed to the BJP by creating “parallel power structures”.

As a mark of protest in 2021, the Bengal Assembly passed a resolution demanding the revocation of the jurisdiction extension. TMC leaders have raised concerns about harassment of locals and the creation of an atmosphere of fear in border districts, further fueling the controversy over the balance of power between state and central authorities.

In January this year, the Supreme Court announced that it would examine the validity of Centre’s 2021 notification to undertake searches, seizures and arrests within the extended 50km stretch compared to earlier limit of 15km.

Trinamool Congress MP from Murshidabad Abu Taher Khan told The Telegraph: “As an MP I daily encounter several complaints of BSF atrocities from people who live in five Assembly segments in my constituency that are near the India-Bangladesh border. BSF personnel have unleashed terror in the bordering villages in these segments. If they in real terms allowed access up to 50km, normal lives of people would be paralysed in fear.”

Senior BSF officials, however, claimed that the central forces prioritised fostering positive relationships with communities near the border.

“We firmly believe that a strong rapport between the locals (local residents) and security forces is essentialto effective border security. Our personnel are well-trained and fully aware of their rights and responsibilities, leaving little room for human rights violations,” said a senior BSF official.

Rights group seeks NHRC intervention after BSF's alleged 'assault' in Bengal

https://www.telegraphindia.com/amp/west-bengal/rights-group-seeks-national-human-rights-commission-intervention-after-border-security-force-alleged-assault-in-bengal/cid/2065613

The organisation claimed such deployments result in unnecessary interference in the daily lives of residents and their livelihood

Subhasish Chaudhuri, Alamgir Hossain

Calcutta, Behrampore | Published 24.11.24, 10:52 AM

A Bengal-based human rights organisation, Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), has appealed to the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene and prevent Border Security Force (BSF) personnel from being posted 8km inside villages from the international border.

The organisation claimed such deployments result in unnecessary interference in the daily lives of residents and their livelihood.

In its petition to the NHRC, with copies sent to the director general of the BSF, the Union ministry of home affairs, and the Bengal police, apart from others, MASUM highlighted a recent incident of alleged “brutal assault” in Murshidabad’s Jalangi area to stress their point.

On November 8, a young fisherman, Anowar Mondal, was reportedly beaten mercilessly by a BSF company commander while fishing near Toltoli ferry ghat. The officer allegedly confiscated and damaged Mondal’s identity card, issued by the Bengal government, rendering it unusable. Senior BSF officials of the South Bengal Frontier, however, refuted the allegations claiming it was “far from truth”.

However, according to the petition, Mondal, a 20-year-old resident of Char-Parashpur village under Ghospara Gram Panchayat, was fishing with others around 6am when the incident occurred. The BSF commander, identified as Shibram from Battalion-46 (Forajipara border outpost), allegedly abused him verbally before assaulting him with a ruler, warning him not to return to the area for fishing.

“This incident not only caused significant physical harm to the young fisherman but also jeopardised his livelihood, instilling fear within his community,” said MASUM secretary Kirity Roy.

Mondal lives in Char-Parashpur, an alluvial stretch of land formed on the other side of the Padma river after his original village was lost to erosion. The villagers, dependent on fishing for their livelihood, rely on BSF clearance to access these areas as they lack the know-how of border demarcations in rivers.

To prevent their harassment, the state government has issued identity cards to these fishermen.

However, Roy alleged that “high-handedness” by BSF personnel has made the villagers live in constant fear.

“The actions of the BSF violate fundamental human rights and constitutional protections, including those ensured under the provisions Article 21 (right to life and personal liberty), Article 19 (freedom of profession), and Article 22 (protection against arbitrary arrest and detention),” he said.

Mondal sought medical treatment at a local hospital and later filed a general diary with the Jalangi police station, which the cops had initially refused. However, no action has been taken by the police.

Contacted, Domkal SDPO Shubham Bajaj claimed ignorance about the incident and promised to look into the matter, including an alleged refusal by Jalangi police to register a complaint initially.

A MASUM fact-finding team visited the area to speak to Mondal and other villagers, who reported widespread fear of the BSF.

Refuting the allegations, BSF South Bengal Frontier DIG Nilotpal Pandey said: “Anowar was observed at night crossing beyond the domination line in the riverine, which is an unfenced stretch of the border. Being familiar with the terrain as a regular visitor, he is well aware of the protocols. BSF personnel maintain an entry point for villagers who frequently access the area, but some individuals attempt to bypass it. Typically, no one ventures into such stretches at night unless driven by illegal intentions. A day before the incident, Anowar Mondal was also spotted beyond the domination line under suspicious circumstances, prompting our personnel to impose restrictions on his movement due to repeated violations.”

“However, his allegations of assault are baseless and can be verified through independent sources,” Pandey said, adding that allegations of damaging his identity card would be looked into.

The incident has reignited debates over the Centre’s decision to extend the BSF’s jurisdiction to a 50km-radius from international border in states like Bengal, Assam, Punjab, Gujarat and Rajasthan.

The Centre called it necessary to curb smuggling and enhance border security.

However, Bengal chief minister Mamata Banerjee and her Trinamool Congress government called it a “direct attack on the federal structure” and an encroachment on state powers. The TMC has also alleged that the move is “politically motivated” and aimed at undermining regional governments opposed to the BJP by creating “parallel power structures”.

As a mark of protest in 2021, the Bengal Assembly passed a resolution demanding the revocation of the jurisdiction extension. TMC leaders have raised concerns about harassment of locals and the creation of an atmosphere of fear in border districts, further fueling the controversy over the balance of power between state and central authorities.

In January this year, the Supreme Court announced that it would examine the validity of Centre’s 2021 notification to undertake searches, seizures and arrests within the extended 50km stretch compared to earlier limit of 15km.

Trinamool Congress MP from Murshidabad Abu Taher Khan told The Telegraph: “As an MP I daily encounter several complaints of BSF atrocities from people who live in five Assembly segments in my constituency that are near the India-Bangladesh border. BSF personnel have unleashed terror in the bordering villages in these segments. If they in real terms allowed access up to 50km, normal lives of people would be paralysed in fear.”

Senior BSF officials, however, claimed that the central forces prioritised fostering positive relationships with communities near the border.

“We firmly believe that a strong rapport between the locals (local residents) and security forces is essentialto effective border security. Our personnel are well-trained and fully aware of their rights and responsibilities, leaving little room for human rights violations,” said a senior BSF official.

DECCAN HERALD, Online, 25.11.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

SP workers on way to protest Kundarki bypoll 'rigging' detained, Akhilesh calls for cognizance

https://www.deccanherald.com/elections/uttar-pradesh/sp-workers-on-way-to-protest-kundarki-bypoll-rigging-detained-akhilesh-calls-for-cognisance-3289826

The police in Sitapur said 35 'suspicious persons' and five vehicles from different districts were stopped during routine checking on the intervening night of Saturday and Sunday with a view to prevent crimes.

Last Updated: 24 November 2024, 15:28 IST

Sitapur, UP: About 35 Samajwadi Party workers were detained in this Uttar Pradesh district early on Sunday when they were travelling to Lucknow from Moradabad to protest against "rigging" in the Kundarki assembly bypoll, a top official said.

Reacting to their detention, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav appealed to President Droupadi Murmi and several institutions, including the Supreme Court, to take immediate cognisance of the matter and ensure that the state's BJP government did not commit any injustice or atrocity against those raising their voices for their right to vote.The police in Sitapur said 35 "suspicious persons" and five vehicles from different districts were stopped during routine checking on the intervening night of Saturday and Sunday with a view to prevent crimes.Action will be taken, according to the rules, if they do not have the relevant vehicle documents, the police added.

Yadav said in a post on X on Sunday, "People who were stopped from casting their votes in public in Kundarki or whose votes were cast by someone else were coming to Lucknow to narrate their plight because there was no one paying heed at the local level."

"This would have exposed the BJP's election scam; that is why they were detained by the Uttar Pradesh Police midway in Sitapur," the Kannauj MP further said in Hindi.The BJP's Ramveer Singh won the Kundarki assembly seat in the bypoll, defeating Mohammad Rizwan of the Samajwadi Party by 1,44,791 votes, the Election Commission said on Saturday.Samajwadi Party chief Yadav also appealed to the president, Supreme Court, Election Commission, National Human Rights Commission, the governor and all newspapers and news channels of the country "to take immediate cognisance of the matter and ensure that the BJP government in Uttar Pradesh does not commit any injustice or atrocity against those who want to raise their voices for their right to vote".

Samajwadi Party national secretary Anoop Gupta alleged that all the people detained had identity cards and documents but the administration was not listening to them.The detained workers are not being allowed to use the toilet. They were also provided any food or refreshments, he alleged.

बंगाल में BSF के कथित 'हमले' के बाद मानवाधिकार समूह ने NHRC से हस्तक्षेप की मांग की

https://jantaserishta.com/local/west-bengal/human-rights-group-seeks-nhrc-intervention-after-alleged-bsf-attack-in-bengal-3660632

Triveni24 Nov 2024 1:40 PM

Calcutta, Behrampore कलकत्ता, बरहामपुर: बंगाल स्थित मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार सुरक्षा मंच (MASUM) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से अपील की है कि वह हस्तक्षेप करे और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से गांवों के अंदर 8 किलोमीटर दूर तैनात होने से रोके। संगठन ने दावा किया कि इस तरह की तैनाती से निवासियों के दैनिक जीवन और उनकी आजीविका में अनावश्यक हस्तक्षेप होता है।

को भेजी गई अपनी याचिका में, जिसकी प्रतियां BSF के महानिदेशक, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बंगाल पुलिस के अलावा अन्य को भेजी गई हैं, MASUM ने अपनी बात पर जोर देने के लिए मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके में कथित "क्रूर हमले" की एक हालिया घटना को उजागर किया।8 नवंबर को, एक युवा मछुआरे, अनवर मंडल को कथित तौर पर टोलटोली फेरी घाट के पास मछली पकड़ते समय BSF कंपनी कमांडर द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। अधिकारी ने कथित तौर पर बंगाल सरकार द्वारा जारी मंडल के पहचान पत्र को जब्त कर लिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह अनुपयोगी हो गया। हालांकि, दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि यह "सत्य से कोसों दूर" है।

हालांकि, याचिका के अनुसार, घोसपारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत चार-परशपुर गांव के निवासी 20 वर्षीय मंडल सुबह 6 बजे के आसपास अन्य लोगों के साथ मछली पकड़ रहे थे, जब यह घटना घटी। बटालियन-46 (फोराजीपारा सीमा चौकी) के शिब्रम के रूप में पहचाने जाने वाले बीएसएफ कमांडर ने कथित तौर पर उन्हें मौखिक रूप से गाली दी और फिर एक रूलर से हमला किया, तथा उन्हें मछली पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में वापस न आने की चेतावनी दी।

सचिव किरीटी रॉय ने कहा, "इस घटना ने न केवल युवा मछुआरे को काफी शारीरिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी आजीविका को भी खतरे में डाल दिया, जिससे उसके समुदाय में भय पैदा हो गया।"मंडल चार-परशपुर में रहते हैं, जो पद्मा नदी के दूसरी ओर भूमि का एक जलोढ़ खंड है, जब उनका मूल गांव कटाव में नष्ट हो गया था। अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर ग्रामीण इन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए बीएसएफ की मंजूरी पर निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें नदियों में सीमा सीमांकन की जानकारी नहीं है। उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने इन मछुआरों को पहचान पत्र जारी किए हैं।

हालांकि, रॉय ने आरोप लगाया कि बीएसएफ कर्मियों की "अत्याचारिता" ने ग्रामीणों को लगातार डर में रहने पर मजबूर कर दिया है।उन्होंने कहा, "बीएसएफ की कार्रवाई मौलिक मानवाधिकारों और

संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करती है, जिसमें अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (पेशे की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण) के तहत सुनिश्चित किए गए अधिकार शामिल हैं।" मंडल ने स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा उपचार की मांग की और बाद में जलांगी पुलिस स्टेशन में एक सामान्य डायरी दर्ज की, जिसे पुलिस ने शुरू में मना कर दिया था। हालांकि, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।संपर्क करने पर, डोमकल एसडीपीओ शुभम बजाज ने घटना के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया और मामले की जांच करने का वादा किया, जिसमें जलांगी पुलिस द्वारा शुरू में शिकायत दर्ज करने से कथित इनकार भी शामिल है।एक मासम तथ्य-खोज दल ने मंडल और अन्य ग्रामीणों से बात करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया, जिन्होंने बीएसएफ के व्यापक भय की सूचना दी।

आरोपों का खंडन करते हुए, बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी नीलोत्पल पांडे ने कहा: "अनवर को रात में नदी के किनारे वर्चस्व रेखा से आगे बढ़ते हुए देखा गया था, जो सीमा का एक बिना बाड़ वाला हिस्सा है। एक नियमित आगंतुक के रूप में इलाके से परिचित होने के कारण, वह प्रोटोकॉल से अच्छी तरह वाकिफ है। बीएसएफ के जवान अक्सर इलाके में आने वाले ग्रामीणों के लिए एक प्रवेश बिंदु बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बायपास करने का प्रयास करते हैं।

आमतौर पर, कोई भी व्यक्ति रात में ऐसे हिस्सों में नहीं जाता है जब तक कि अवैध इरादों से प्रेरित न हो। घटना से एक दिन पहले, अनवर मंडल को भी संदिग्ध परिस्थितियों में वर्चस्व रेखा से आगे देखा गया था, जिससे हमारे कर्मियों को बार-बार उल्लंघन के कारण उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया गया।" पांडे ने कहा, "हालांकि, हमले के उनके आरोप निराधार हैं और स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं," उन्होंने कहा कि उनके पहचान पत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच की जाएगी। इस घटना ने बंगाल, असम, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के दायरे तक बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के फैसले पर बहस को फिर से हवा दे दी है। केंद्र ने तस्करी पर अंकुश लगाने और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे जरूरी बताया।हालांकि, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे "संघीय ढांचे पर सीधा हमला" और राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण बताया। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कदम "राजनीति से प्रेरित" है और इसका उद्देश्य "समानांतर सत्ता संरचनाएं" बनाकर भाजपा का विरोध करने वाली क्षेत्रीय सरकारों को कमजोर करना है।

2021 में विरोध के तौर पर, बंगाल विधानसभा ने अधिकार क्षेत्र विस्तार को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। टीएमसी नेताओं ने स्थानीय लोगों के उत्पीड़न और सीमावर्ती जिलों में भय का माहौल पैदा करने की चिंता जताई है, जिससे राज्य और केंद्रीय अधिकारियों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर विवाद और बढ़ गया है।इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वह केंद्र की वैधता की जांच करेगा।

संभल : चार मौतें, सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी, 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री बंद, चंद्रशेखर ने किया घुसने का ऐलान

https://www.agniban.com/sambhal-arson-and-stone-pelting-on-the-streets-entry-of-outsiders-banned-till-december-1-chandrashekhar-announced-to-enter/#goog_rewarded

November 25, 2024 Kalyan Singh

संभल. उत्तर प्रदेश (UP) के संभल (Sambhal) में रविवार को भारी हिंसा हुई. जामा मस्जिद (Jama Masjid) के सर्वे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों (Protesters) और पुलिस (Police) के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 सुरक्षाकर्मियों और प्रशासन के चार कर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए. इस दौरान पत्थर-ईंटें फेंके गए, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया.

20 पुलिसकर्मी घायल, डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर

मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि उपद्रवियों ने गोलियां चलाईं, एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी, सीओ को छर्रे लगे और हिंसा में 20 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल के सिर में भी गंभीर चोट आई है, जबकि डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिला प्रशासन ने 25 नवंबर को कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है. डीएम के आदेश पर 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है, इसे लेकर शहर की सीमा सील कर दी गई है.

संभल हिंसा में इन 4 लोगों की गई जान

संभल हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई. नौमान और बिलाल अंसारी को रात 11 बजे सुपुर्द-ए-खाक किया गया. हिंसा को लेकर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में शिकायत की गई है. एक निजी संस्था ने संभल में पुलिस की फायरिंग से 4 युवकों की मौत का आरोप लगाते हुए वीडियो भी आयोग को भेजा गया है.

चंद्रशेखर आजाद ने किया आज संभल जाने का ऐलान

एक ओर संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, वहीं, भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वह सोमवार यानी आज संभल जाएंगे और मृतकों के परिजनों से मिलेंगे. चंद्रेशखर आजाद ने X पर लिखा कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं. यह कोई मिथक नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है, जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. चाहे वह एससी/एसटी

आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या सीएए विरोधी आंदोलन... हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है. मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा.

अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट में कहा कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साज़िश का 'सर्वोच्च न्यायालय' तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाज़ों को ले गए, उनके ख़िलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुक़दमा दर्ज हो. उनके ख़िलाफ़ 'बार एसोसिएशन' भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे. अखिलेश ने कहा कि उप्र शासन-प्रशासन से न कोई उम्मीद थी, न है.

हिंसा में सड़क पर बिखरे चप्पल, ईंटें और पत्थर

हिंसा की तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को इमारतों की छतों और शाही जामा मस्जिद के सामने से पुलिस पर पथराव करते हुए देखा गया. एक गली में बड़ी संख्या में चप्पलें, ईंटें और पत्थर बिखरे हुए थे. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ पुलिसकर्मी एक गली की ओर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है. एक क्लिप में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार को पथराव करने वालों से हिंसा न करने का आग्रह करते हुए देखा जा सकता है. उन्हें अपने मेगाफोन पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि इन राजनेताओं के लिए अपना भविष्य खराब मत करो.

2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया

संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया है, किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे किसी की जान जा सकती हो. 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनके पास से कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं. जिस जगह पर फायरिंग हुई, वहां से कई अलग-अलग बोर के गोले बरामद किए गए हैं. हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से भी हथियार बरामद किए गए हैं.

हिंसा में शामिल लोगों पर लगेगा NSA

नखासा थाना क्षेत्र के एक घर से फायरिंग हुई, जहां से दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. मंगलवार से ही संभल में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जब एक स्थानीय अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था. याचिका में दावा किया गया था कि उस जगह पर हरिहर मंदिर था. अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि दो महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है, हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

संभल की घटना की मानवाधिकार आयोग से शिकायत:पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग का आरोप, याचिका दर्ज

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/rampur/news/complaint-to-human-rights-commission-about-sambhal-incident-134012446.html

रामपुर10 घंटे पहले

-

संभल में हुई हिंसक घटना के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई है। फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों की मौत हुई, जोकि मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने इस याचिका को पंजीकृत कर लिया है।

वीडियो को बनाया आधार

डीके फाउंडेशन ने अपनी याचिका में कथित वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद सर्वे का आदेश आने के बाद जिले का माहौल बिगड़ गया और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

फाउंडेशन का आरोप-पुलिस की कार्रवाई एकतरफा

फाउंडेशन के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार और हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता सैफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए सिर्फ एक पक्ष (मुस्लिम समुदाय) के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने दावा किया कि फायरिंग में तीन युवकों की मौत हुई, जो कि निष्पक्ष जांच की मांग करता है।

याचिका में पुलिस पर गंभीर आरोप

याचिका में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि प्रशासन ने हिंसा रोकने के बजाय इसे बढ़ावा दिया। सैफ मोहम्मद खान ने इसे "निंदनीय" और "बड़ी जांच का विषय" बताया।

आयोग में याचिका पंजीकृत

डीके फाउंडेशन के अनुसार, उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में दिए गए प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब पुलिस की कार्रवाई की जांच और घटना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

संभल में शांति की अपील

इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। डीके फाउंडेशन ने न्यायिक जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।